खेनयेई

बनाम

न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड और अन्य

(2015 का सिविल अपील सं. 4244 आदि)

07 मई, 2015।

[भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा.]

अपकृत्य– समग्र लापरवाही– संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के संयुक्त गलत कार्य के कारण लगी चोटें—मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व– माना गया: ऐसे मामलों में, दायित्व संयुक्त और अलग है– दावेदार को सबसे आसान लक्ष्य/विलायक प्रतिवादी से पूरी राशि वसूल करने का अधिकार है—दावेदार की तुलना में लापरवाही की सीमा का निर्धारण करके अपकृत्यकर्ताओं के बीच मुआवजे का बंटवारा स्वीकार्य नहीं है– उनकी लापरवाही की सीमा का निर्धारण केवल उनके पारस्परिक दायित्व के प्रयोजन के लिए है।

लापरवाही - अंशदायी लापरवाही और समग्र लापरवाही - के बीच अंतर।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1.1 संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं की लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना के मामले में, वे सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य में सहायता या सलाह देते हैं या निर्देश देते हैं या उसमें शामिल होते हैं, उत्तरदायी हैं। ऐसे मामले में देनदारी हमेशा संयुक्त

और अलग से होती है। ऐसे मामले में संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं की लापरवाही की सीमा वादी/दावेदार के दावे की संतुष्टि के लिए महत्वहीन है और इसे अदालत द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। वादी/दावेदार की तुलना में प्रत्येक संयुक्त अपकृत्यकर्ता का दायित्व विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संयुक्त और अलग दायित्व है। समग्र लापरवाही के मामले में, वादी को भुगतान करने के लिए अपकृत्य करने वालों के बीच मुआवजे का बंटवारा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वादी/दावेदार को सबसे आसान लक्ष्य/विलायक प्रतिवादी से पूरी राशि वसूल करने का अधिकार है। [पैरा 4] [163-जी-एच; 164-ए-सी]

1.2 यदि सभी संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं को पक्षकार बना दिया गया है और साक्ष्य पर्याप्त है, तो यह अदालत/न्यायाधिकरण के लिए खुला है कि वह ड्राइवरों की समग्र लापरवाही की परस्पर सीमा निर्धारित कर सके। हालाँकि, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के बीच लापरवाही की सीमा का निर्धारण केवल उनके पारस्परिक दायित्व के प्रयोजन के लिए है ताकि एक व्यक्ति वादी/दावेदार को पूरा भुगतान करने के बाद दूसरे से उस सीमा तक राशि वसूल कर सके, जिस हद तक उसने दूसरे के दायित्व को पूरा किया है। यदि उन दोनों को पक्षकार बनाया गया है और उनकी लापरवाही का बंटवारा/सीमा अदालत/न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की गई है, तो मुख्य मामले में, एक संयुक्त अपकृत्यकर्ता निष्पादन कार्यवाही में दूसरे से राशि वसूल कर सकता है। [पैरा 18] 178-जी-एच; 179-ए-बी]

1.3 अदालत/न्यायाधिकरण के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अन्य संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं को दोषी ठहराए जाने की अनुपस्थिति में दो वाहनों के चालकों की समग्र

लापरवाही की सीमा निर्धारित करे। ऐसे मामले में, डिक्री या आदेश पारित होने के बाद स्वतंत्र कार्यवाही में अन्य संयुक्त अपकृत्यकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए, यदि वह चाहे तो, पक्षकार संयुक्त अपकृत्यकर्ता को छोड़ दिया जाना चाहिए। [पैरा 18) [179-सी]

1.4 वर्तमान मामले में, संबंधित ड्राइवरों के 2/3 और 1/3 की लापरवाही की सीमा तक समग्र लापरवाही के पारस्परिक दायित्व का निर्धारण होता है। इस प्रकार, वाहन-ट्रेलर-ट्रक जिसका बीमाकर्ता के पास बीमा नहीं था, दो-तिहाई की सीमा तक लापरवाह था। दावेदार को भुगतान करने के बाद बस का बीमा करने वाला बीमाकर्ता निष्पादन कार्यवाही में ट्रेलर-ट्रक के मालिक से उपरोक्त सीमा तक राशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि साक्ष्य के अभाव में पारस्परिक दायित्व का कोई निर्धारण नहीं किया गया था या अन्य संयुक्त अपकृत्यकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया था, तो ऐसे विवाद को निपटाने और निष्पादन कार्यवाही में राशि की वसूली करना खुला नहीं था, लेकिन उपाय यह होगा कि कानून के अनुसार कोई अन्य मुकदमा या उचित कार्यवाही दायर करें। [पैरा 18] [178-बी-डी]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चल्ला भारतम्मा एवं अन्य 2004 (8) एससीसी 517: 2004 (4) पूरक एससीआर 587; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नंजप्पन एवं अन्य 2004 (13) एसईसी 224: 2004 (2) एससीआर 365––पर भरोसा किया गया।

कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, बैंगलोर और आदि बनाम अरुण उर्फ अरविंद और आदि आदि एआईआर 2004 कर्नाटक 149; श्रीमती सुशीला भदोरिया एवं

अन्य बनाम म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य 2005 (1) एमपीएलजे 372 – स्वीकृत किया गया।

पालघाट कोयंबटूर ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड बनाम नारायणन आईएलआर (1939) मद्रास 306; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पी ए वर्गीस एवं अन्य 1991(1)एसीसी226; यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम वर्गीस एवं अन्य 1989 2 एसीसी 483= 1989 एसीजे 472; यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम यू ई प्रसाद एवं अन्य एआईआर 1985 कर्नाटक 160; आंध्र मरीन एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम पी राधाकृष्णन और अन्य एआईआर 1984 मद्रास 358; श्रीमती कुन्दन बाला वोरा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1983 इलाहबाद 409; नारायण देवी और अन्य बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य 19892 एसीसी 116(दिल्ली=1989 एसीजे 1118; गणेश बनाम सैयद मुन्नेद अहमद और अन्य आईएलआर (1999) कर्नाटक 403; हीराबेन भागा और अन्य बनाम गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम 1982 एसीजे (पूरक) 414 (गुजरात)-संदर्भित किया गया।

जी.एन.ई.आर. बनाम हार्ट (2003) ईडब्ल्यूएचसी 2450 (क्यूबी); लॉ ऑफ़ टॉर्ट्स बाय पोलोक 15 वां संस्करण; परफॉर्मेंस कार्स लिमिटेड बनाम अब्राहम (1962 (1) क्यूबी 33); बेकर बनाम विलोबी 1970 ए.सी. 467; मॉर्टगेज एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम बोवरमैन एंड पार्टनर्स 1996 (2) ऑल ई.आर. 836 आदि—संदर्भित किया गया।

लॉ ऑफ़ टॉर्ट्स द्वितीय संस्करण, 1992 बाय जस्टिस जी.पी. सिंह; लॉ ऑफ़ टॉर्ट्स बाय विनफील्ड और जोलोविज़ 17 वां संस्करण, 2006; रोजर्स ऑन यूनीफिकेशन ऑफ टॉर्ट लॉ: मल्टीपल टॉर्टफेसर्स– संदर्भित किया गया।

2. अंशदायी और समग्र लापरवाही के बीच अंतर है। अंशदायी लापरवाही के मामले में, जिस व्यक्ति ने स्वयं इस हद तक योगदान दिया है, वह अपनी लापरवाही की सीमा तक दुर्घटना में लगी चोटों के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है, जबकि समग्र लापरवाही के मामले में, पीड़ित व्यक्ति ने दुर्घटना में योगदान नहीं दिया है, बल्कि दो या दो से अधिक अन्य व्यक्तियों की लापरवाही के संयोजन का परिणाम है। [पैरा 14) (172-एफ-एच)

टी.ओ. एंथोनी बनाम करवर्नन और अन्य 2008 (3) एससीसी 748: 2008 (2) एससीआर 291; आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम के हेमलता एवं अन्य 2008 (6) एससीसी 767: 2008 (8) एससीआर 1201; पवन कुमार और अन्य बनाम हरकिशन दास मोहन लाल और अन्य 2014 (3) एसईसी 590 = 2014 (4) एससीआर 1; मछिंद्रनाथ केरनाथ कसार बनाम डी.एस मायलारप्पा और अन्य 2008 (13) सेकंड 198: 2008 (7) एससीआर 83––पर भरोसा किया गया।

निर्णय विधि संदर्भ

आईएलआर (1939) मद्रास 306	संदर्भित किया गया	पैरा 8
1991(1) एसीसी 226	संदर्भित किया गया	पैरा 9
1989 एसीजे 472	संदर्भित किया गया	पैरा 9
एआईआर 1985 कर्नाटक 160	संदर्भित किया गया	पैरा 9
एआईआर 1984 मद्रास 358	संदर्भित किया गया	पैरा 9
एआईआर 1983 इलाहबाद 409	संदर्भित किया गया	पैरा 9

1989 एसीजे 1118	संदर्भित किया गया	पैरा 9
एआईआर 4 कर्नाटक 149	स्वीकृत किया गया	पैरा 10
आईएलआर (1999) कर्नाटक 403	संदर्भित किया गया	पैरा 9
1982 एसीजे (पूरक) 414 (गुजरात)	संदर्भित किया गया	पैरा 11
2005 (1) एमपीएलजे 372	स्वीकृत किया गया	पैरा 12
2008 (2) एससीआर 291	भरोसा किया गया	पैरा 14
2008 (8) एससीआर 1201	भरोसा किया गया	पैरा 15
2014 (4) एससीआर 1	भरोसा किया गया	पैरा 16
2008 (7) एससीआर 83	भरोसा किया गया	पैरा 16
2004 (4) पूरक एससीआर 587	भरोसा किया गया	पैरा 16
2004 (2) एससीआर 365	भरोसा किया गया	पैरा 17

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4244/2015

कोहिमा पीठ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 2007 की एमएसी अपील सं. 42(के) /2009 में दिनांक 22.02.2010 के निर्णय और आदेश से।

साथ में

2015 की सिविल अपील क्रमांक 4245, 4246, 4247, 4248, 4249 और 4250

अनुपम लाल दास, अरुनभ चौधरी, गैनलुंग पनमेई, अनिरुद्ध सिंग, कर्मा दोरजी अपीलार्थी के लिए।

एम के दुआ उत्तरदाता के लिए।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलों में, मुख्य प्रश्न जो विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या दावेदार के लिए संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से किसी एक से संपूर्ण मुआवजा वसूल करने का अधिकार है, खासकर तब जब दुर्घटना में ट्रेलर-ट्रक और बस के ड्राइवरों की संयुक्त लापरवाही क्रमशः 2/3 और 1/3 हद तक पाई गई हो।

3. तत्काल मामलों में दावेदारों को चोटें तब लगीं जब दो वाहन—बस और ट्रेलर-ट्रक एक-दूसरे से टकरा गए। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निश्चित रूप से बस का बीमाकर्ता है। हालाँकि, अतिरिक्त सबूतों के आधार पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ट्रेलर-ट्रक का बीमाकर्ता नहीं है, इसलिए पुरस्कार के 2/3 हिस्से को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

4. यह समग्र लापरवाही का मामला है जहां संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के संयुक्त गलत कार्य के कारण दावेदारों को चोटें आई हैं। संयुक्त अपकृत्य कर्ताओं की लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना के मामले में, वे सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य में सहायता या सलाह देते हैं या निर्देशन करते हैं या उसमें शामिल होते हैं, उत्तरदायी हैं। ऐसे मामले में देनदारी हमेशा संयुक्त और अलग होती है। ऐसे मामले में संयुक्त अपकृत्य कर्ता की

लापरवाही की सीमा वादी/दावेदार के दावे की संतुष्टि के लिए महत्वहीन है और इसे अदालत द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि सभी संयुक्त अपकृत्यकर्ता अदालत के समक्ष हैं, तो यह उचित स्तर पर उनके बीच अंतर-इक्विटी को समायोजित करने के उद्देश्य से उनके दायित्व की सीमा निर्धारित कर सकता है। वादी/दावेदार की तुलना में प्रत्येक संयुक्त अपकृत्य कर्ता का दायित्व विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संयुक्त और अलग दायित्व है। समग्र लापरवाही के मामले में, वादी को भुगतान करने के लिए अपकृत्य करने वालों के बीच मुआवजे का बंटवारा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वादी/दावेदार को सबसे आसान लक्ष्य/विलायक प्रतिवादी से पूरी राशि वसूल करने का अधिकार है।

5. न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, द्वितीय संस्करण, 1992 में, यह देखा गया है कि समग्र लापरवाही में, दो अपकृत्यकर्ताओं के बीच मुआवजे का बंटवारा स्वीकार्य नहीं है।

6. विनफील्ड और जोलोविज़ द्वारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, 17 वां संस्करण, 2006 में, लेखक ने परफॉर्मेंस कार्स लिमिटेड बनाम अब्राहम [1962 (1) क्यूबी 33], बेकर बनाम विलोबी 1970 एसी 467, रोजर्स ऑन यूनिफिकेशन ऑफ टॉर्ट लॉ: मल्टीपल टॉर्टफेसर्स; जीएनईआर बनाम हार्ट [2003] ईडब्ल्यूएचसी 2450 (क्यूबी), मॉर्गेज एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम बोवरमैन एंड पार्टनर्स 1996 (2) आल ईआर 836 आदि का संदर्भ दिया है और इस प्रकार देखा:

> "जहां दो या दो से अधिक लोग दावेदार के प्रति अपने कर्तव्य के स्वतंत्र उल्लंघन के कारण उसे अलग-अलग चोटें पहुंचाते हैं, वहां

किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक अत्याचारी उस क्षति के लिए उत्तरदायी होता है जो उसने किया है और केवल उस क्षति के लिए। हालाँकि, जहां अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा कर्तव्य के दो या दो से अधिक उल्लंघनों के कारण दावेदार को एक ही, अविभाज्य चोट का सामना करना पड़ता है, स्थिति अधिक जटिल होती है। ऐसे मामले में कानून यह है कि दावेदार अपने नुकसान की पूरी राशि के लिए उनमें से सभी या उनमें से किसी पर मुकदमा करने का हकदार है, और कहा जाता है कि प्रत्येक इसके लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी है। यदि दावेदार प्रतिवादी ए पर मुकदमा करता है, लेकिन बी और सी पर नहीं, तो ए के लिए यह खुला है कि वह अपनी सापेक्ष जिम्मेदारी के संबंध में बी और सी से "योगदान" मांग सकता है, लेकिन यह ए, बी और सी के बीच का मामला है और दावेदार को प्रभावित नहीं करता है। इसकामतलब यह है कि उस नुकसान के संबंध में क्रमिक कार्रवाइयों की संभावनाओं और एक यातनाकर्ता द्वारा दूसरों के खिलाफ योगदान या क्षतिपूर्ति के दावों से निपटने के लिए विशेष नियम आवश्यक हैं। दावेदार के लिए यह दिखाना बहुत फायदेमंद हो सकता है कि उसे कई प्रतिवादियों के हाथों समान, अविभाज्य नुकसान हुआ है, क्योंकि इससे वह उन मामलों में निहित जोखिम से बच जाता है, जहां अलग-अलग चोटें होती हैं, यह पता चलने पर कि एक प्रतिवादी दिवालिया है (या बीमा रहित) और

उसके विरुद्ध निर्णय निष्पादित करने में असमर्थ होना। यहां तक कि जहां सभी प्रतिभागी विलायक हैं, एक ऐसी प्रणाली जो दावेदार को नुकसान के आनुपातिक हिस्से के लिए प्रत्येक पर मुकदमा करने में सक्षम बनाती है, उसे कई कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता होगी, जिनमें से कुछ में दायित्व, कारण और सबूत के जटिल मुद्दे शामिल हो सकते हैं। जैसा कि अब कानून है, दावेदार आसानी से "सबसे आसान लक्ष्य" के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकता है। निस्संदेह, वही तस्वीर सॉल्वेंट प्रतिवादी के दृष्टिकोण से इतनी आकर्षक नहीं है, जो अंततः उस नुकसान के लिए पूरी ज़िम्मेदारी ले सकता है जिसके कारण उसने केवल आंशिक, यहां तक कि माध्यमिक भूमिका निभाई थी। इस प्रकार एक वकील अपने ग्राहक को यह बताने में विफल रहने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो सकता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि जिस मूल्यांकन पर ग्राहक उधार देने का प्रस्ताव करता है वह संदिग्ध है, मूल्यांकनकर्ता दिवालिया है; और कंपनी ऑडिट के दौरान धोखाधड़ी का पता लगाने में लापरवाही से विफलता के लिए ऑडिटर को पूरी जिम्मेदारी लेने की संभावना होगी। इस देश में कुछ पेशेवर निकायों द्वारा संयुक्त और अलग दायित्व के नियम के खिलाफ एक निरंतर अभियान चलाया गया है, जिन्होंने इसके बजाय "आनुपातिक दायित्व" की व्यवस्था के लिए तर्क दिया है, जिससे दावेदार के खिलाफ, न कि केवल एक समूह के रूप में प्रतिवादियों के

बीच, प्रत्येक प्रतिवादी दायित्व का केवल अपना हिस्सा वहन करेगा। हालाँकि यहाँ यह सुझाव नहीं दिया गया है कि इस तरह के बदलाव को व्यक्तिगत चोट के दावों तक बढ़ाया जाना चाहिए, यह कुछ अमेरिकी न्यायालयों में हुआ है, चाहे क़ानून द्वारा या न्यायिक निर्णय द्वारा। हालाँकि, 1996 में व्यापार और उद्योग विभाग की ओर से विधि आयोग द्वारा इस मुद्दे की जांच से यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान कानून आनुपातिक दायित्व के विभिन्न रूपों के लिए बेहतर था।"

7. लॉ ऑफ टॉर्ट्स, 151वें संस्करण में पोलक ने समग्र लापरवाही की अवधारणा पर चर्चा की है। पृष्ठ 361 पर प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

"एक अन्य प्रकार का प्रश्न उठता है जहां एक व्यक्ति अपनी गलती के बिना घायल हो जाता है, लेकिन दो व्यक्तियों की लापरवाही के संयुक्त प्रभाव से, जिनमें से एक दूसरे के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। यह माना गया है कि ए, जेड के विरुद्ध, जो कि अपनी ओर से उचित देखभाल के अभाव में घायल हो गया है, किसी तीसरे व्यक्ति B की तथाकथित अंशदायी लापरवाही से अपना लाभ उठा सकता है। यह सच है कि आप मेरी लापरवाही से घायल हुए थे , लेकिन ऐसा नहीं होता अगर बी ने भी लापरवाही नहीं की होती, इसलिए, आप मुझ पर या बी से अलग किसी भी घटना पर मुकदमा नहीं कर सकते। हालिया प्राधिकारी निश्चित रूप से इस तरह के बचाव की अनुमति देने के खिलाफ है, और मामलों के एक विशेष वर्ग में इस को सशक्त रूप से

अस्वीकृत कर दिया गया है। हालाँकि, ए को जेड को उत्तर देने के लिए खुला होना चाहिए: आप मेरी लापरवाही से बिल्कुल भी घायल नहीं हुए थे, बल्कि केवल और पूरी तरह से B की लापरवाही से घायल हुए थे। ऐसा लगता है कि यह कानून के बजाय तथ्य का प्रश्न है (जैसा कि, जूरी के विवेक की सामान्य सीमा के भीतर, निकटतम कारण का प्रश्न सभी सामान्य मामलों में होता है) क्षति के बीच, प्रकार और डिग्री में संबंध की संबंधित डिग्री क्या है जेड द्वारा और ए और बी के स्वतंत्र लापरवाह आचरण से यह कहना उचित हो जाएगा कि जेड अकेले ए की लापरवाही से, या अकेले बी की, या ए और बी दोनों की लापरवाही से घायल हुआ था। लेकिन अगर इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, तो अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जेड, ए और बी दोनों पर मुकदमा कर सकता है।

पृष्ठ 362 पर लेखक ने कहा है:-

"घटना के निकटतम या तत्काल कारण का सख्त विश्लेषण: जांच जो उचित देखभाल के अभ्यास से शरारत को रोक सकती थी, केवल तभी प्रासंगिक है जहां प्रतिवादी कहता है कि वादी को अपनी लापरवाही से नुकसान उठाना पड़ा। जहां दो या दो से अधिक स्वतंत्र व्यक्तियों के लापरवाह कृत्यों के कारण किसी तीसरे को नुकसान हुआ हो, पीड़ित को यह पता लगाने के लिए ऐसा कोई विश्लेषण करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है कि वह किस पर मुकदमा कर सकता है।

निस्संदेह, क्षति की दूरदर्शिता के संबंध में सामान्य नियमों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर, वह सभी या किसी भी लापरवाह व्यक्ति पर मुकदमा करने का हकदार है। उसे इससे कोई सरोकार नहीं है कि उन व्यक्तियों के बीच योगदान या क्षतिपूर्ति का कोई कर्तव्य है या नहीं, हालाँकि किसी भी स्थिति में वह अपनी पूरी क्षति से अधिक की वसूली नहीं कर सकता है।"

8. पालघाट कोयंबटूर ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड बनाम नारायणन, [आईएलआर (1939) मद्रास 306] में, यह माना गया है कि जहां चोट दो पक्षों के गलत कार्य के कारण होती है, वादी यह पता लगाने के लिए घटना के निकटतम या तात्कालिक कारण का कड़ाई से विश्लेषण करने के लिए बाध्य नहीं है कि वह किस पर मुकदमा कर सकता है। क्षति की दूरी के नियमों के अधीन, वादी सभी या किसी भी लापरवाह व्यक्ति पर मुकदमा करने का हकदार है और उसे इससे कोई सरोकार नहीं है कि उन व्यक्तियों के बीच योगदान या क्षतिपूर्ति का कोई कर्तव्य है या नहीं, हालाँकि किसी भी स्थिति में वह अपनी पूरी क्षति से अधिक की भरपाई नहीं कर सकता। उसे किसी भी प्रतिवादी से क्षति की पूरी राशि वसूल करने का अधिकार है।

9. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पीए वर्गीस और अन्य [1991 (1)एसीसी 226] में, यह देखा गया है कि समग्र लापरवाही का मामला तब होता है जब दुर्घटना होती है और परिणामस्वरूप चोटें और क्षति दावेदार की कोई लापरवाही के बिना होती है लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ओर से लापरवाही के परिणामस्वरूप। ऐसे मामले में, ट्रिब्यूनल को दोनों वाहनों के मालिकों के खिलाफ एक समग्र डिक्री पारित

करनी चाहिए। यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम वर्गीस एवं अन्य में [1989 2 एसीसी 483 = 1989 एसीजे 472], यह देखा गया है कि समग्र लापरवाही के मामले में, घायल के पास सभी या किसी संयुक्त अत्याचारी के खिलाफ कार्यवाही करने का विकल्प होता है। इसलिए, बीमाकर्ता यह बचाव नहीं कर सकता कि कार्रवाई टिकाऊ नहीं है क्योंकि अन्य संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं को पक्ष नहीं बनाया गया है। यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम यूई प्रसाद एंड अन्य [एआईआर 1985 कर्नाटक 160] में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। आंध्र मरीन एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम पी. राधाकृष्णन और अन्य [एआईआर 1984 मद्रास 358] मामले में, यह माना गया है कि समग्र लापरवाही के मामले में हर गलत काम करने वाला पूरे नुकसान के लिए उत्तरदायी है, अगर इसे अन्यथा बनाया गया हो।

श्रीमती कुन्दन बाला वोरा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1983 इलाहबाद 409] में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया है जहां बस और कार के बीच टक्कर हुई थी। दोनों चालकों की लापरवाही पाई गई। यह माना गया कि वे पूरे नुकसान का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे। नारायण देवी और अन्य बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य [1989 2 एसीसी 116 (डेल.) = 1989 एसीजे 1118] में एक दुर्घटना में शामिल दो ट्रकों के ड्राइवरों द्वारा समग्र लापरवाही का मामला था, जिसने टेम्पो को दो तरफ से टक्कर मार दी थी। दोनों वाहनों ने किस अनुपात में कदाचार किया या कुपित किया, यह तय नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह

माना गया कि ट्रिब्यूनल अपकृत्यकर्ताओं के दायित्व को संयुक्त और अलग के रूप में मानने में सही था।

10. कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, बैंगलोर और आदि बनाम अरुण उर्फ अरविंद और आदि आदि [एआईआर 2004 149] में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने गणेश बनाम सैयद मुन्नेद अहमद और अन्य [आईएलआर (1999) कर्नाटक 403] में उसी उच्च न्यायालय की एक और पूर्ण पीठ के फैसले की पुष्टि की है। एक खंड पीठ ने निम्नलिखित दो प्रश्नों पर गणेश के मामले (ऊपर) में निर्णय को बड़ी पीठ को संदर्भित किया:

> "1. यदि कार्यवाही अंततः ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए एक आदेश के साथ निर्धारित की जाती है और कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा उसी के खिलाफ अपील द्वारा निपटाई जाती है, तो क्या न्यायाधिकरण अपकृत्यकर्ता को पक्षकार बनाने या उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने जैसी किसी भी आगे की कार्यवाही को कानूनी रूप से अस्वीकार्य बनाने के लिए अधिकारहीन नहीं बन जाता है?
>
> 2. उस अपकृत्यकर्ता के लिए क्या उपाय है जिसने आदेश को तुष्ट कर दिया है, लेकिन जो उस वाहन का विवरण नहीं जानता जो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था?"

11. केएसआरटीसी बनाम अरुण उर्फ अरविंद (ऊपर) में एक पूर्ण पीठ ने उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए पाया कि यह समग्र लापरवाही का मामला था और अपकृत्य करने वालों का दायित्व संयुक्त और अलग था। इसलिए, भले ही अपकृत्य करने वालों में से

किसी एक का कार्यान्वयन न हो, दावेदार ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित पूर्ण मुआवजे का हकदार था। पूर्ण पीठ ने हीराबेन भागा एवं अन्य बनाम गुजरात स्टेट रोड परिवहन निगम [1982 एसीजे (सप्र.) 414 (गुजरात)] मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यह पूरी तरह से दावेदार की पसंद है कि वह दोनों संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं को या उनमें से किसी एक को पक्षकार बनाएगा। संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से किसी एक को पक्षकार बनाने में दावेदार के असफल होने पर, गैर-अभियुक्त संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं की लापरवाही की सीमा तक दावेदार पर अंशदायी दायित्व नहीं डाला जा सकता है। यह उन संयुक्त अपकृत्य कर्ताओं के लिए है, जिन्हें मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, अन्य संयुक्त अपकृत्य कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था। डिक्री या आदेश दिए जाने के बाद अन्य के दायित्व की सीमा तक वसूलने के लिए अन्य गलत कर्ता पर मुकदमा करने के लिए संयुक्त अपकृत्य कर्ता के लिए यह खुला है। यह निर्धारित किया गया है कि गणेश के मामले (ऊपर) में कानून सही ढंग से निर्धारित किया गया है और सभी संयुक्त अपकृत्य कर्ताओं को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है और सभी संयुक्त अपकृत्य कर्ताओं को पक्षकार बनाने में विफलता के कारण, मुआवजे को गैर-अभियुक्त अपकृत्य कर्ता की लापरवाही की सीमा तक कम नहीं किया जा सकता है। संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से किसी एक को पक्षकार न बनाना दावेदार को देय मुआवजे को कम करने का बचाव नहीं है। हमारी राय में, ऐसा प्रतीत होता है कि कानून केएसआरटीसी बनाम अरुण उर्फ अरविंद (ऊपर) में सही ढंग से घोषित किया गया है।

12. श्रीमती सुशीला भदोरिया और अन्य बनाम एमपी राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य [2005 (1) एमपीएलजे 372] में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह भी निर्धारित किया है कि समग्र लापरवाही के मामले में, दायित्व संयुक्त और अलग है और वाहन के चालक, मालिक और बीमाकर्ता को किसी एक संयुक्त अपकृत्यकर्ता से पूरी राशि वसूलने के लिए पक्षकार बनाया जा सकता है। बंटवारे के संबंध में भी, यह देखा गया है कि दोनों वाहन संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। एक बार लापरवाही और मुआवजे का निर्धारण हो जाने के बाद, दोनों के बीच मुआवजे का बंटवारा करना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गवाह बॉक्स में उपस्थित दोनों वाहनों के चालकों की अनुपस्थिति में बंटवारे का निर्धारण करना मुश्किल है। इसलिए, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के बीच दावे का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। पूर्ण पीठ के निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां दिया गया है:

> "जब चोट दो संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं की लापरवाही के परिणामस्वरूप होती है, तो दावेदार को दायित्व के अनुपात के संबंध में सटीक व्यक्ति पर अपनी उंगली रखने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक संयुक्त अपकृत्यकर्ता के कार्य को अलग करने के लिए न्यायालय को सक्षम करने वाले किसी भी साक्ष्य के अभाव में, दोनों अपकृत्यकर्ता पर संयुक्त रूप से दायित्व तय किया जा सकता है और यदि संयुक्त अपकृत्यकर्ता में से केवल एक को पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है, तो संपूर्ण दायित्व संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से एक पर बांधा जा सकता है। यदि दोनों संयुक्त अपकृत्यकर्ता न्यायालय के समक्ष हैं और प्रत्येक

अपकृत्यकर्ता के कृत्य के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं और न्यायालय के लिए दोनों संयुक्त अपकृत्यकर्ता द्वारा लापरवाही की सटीक प्रकृति पर विचार करते हुए दावे को विभाजित करना संभव है, तो वह दावे का बंटवारा कर सकता है। हालाँकि, जब संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं की लापरवाही का अनुपात निर्धारित करना संभव नहीं है, तो दावे को विभाजित करना आवश्यक नहीं है। ऐसे मामलों में, संयुक्त अपकृत्यकर्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

इसी सिद्धांत पर, संयुक्त अपकृत्य के मामले में जहां दायित्व संयुक्त और अलग है, यह दावेदार की पसंद है कि वह दोनों वाहनों या उनमें से किसी एक के मालिक और चालक और बीमाकर्ता से नुकसान का दावा करे। यदि उनमें से किसी एक के खिलाफ दावा किया जाता है, तो चोट या मृत्यु के कारण मुआवजे की पूरी राशि उस वाहन के मालिक, चालक और बीमाकर्ता के खिलाफ लगाई जा सकती है क्योंकि उनका दायित्व संयुक्त और अलग है और दावेदार इनमें से किसी एक से राशि वसूल कर सकता है। रिकॉर्ड पर उचित और ठोस साक्ष्य के अभाव में प्रत्येक अपकृत्यकर्ता के दावे का बंटवारा नहीं किया जा सकता है और दावे का बंटवारा करना आवश्यक नहीं है।

संक्षेप में, हम निम्नानुसार मानते हैं:-

(i) किसी एक वाहन के मालिक, चालक और बीमाकर्ता पर मुकदमा दायर किया जा सकता है और दोनों वाहनों के मालिक, चालक और बीमाकर्ता पर मुकदमा करना आवश्यक नहीं है। दावेदार दोनों वाहनों के मालिक, ड्राइवर और बीमाकर्ता या उनमें से किसी को भी पक्षकार बना सकता है।

(ii) संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के दायित्व का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। यदि दोनों संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं को पार्टी के रूप में शामिल किया गया है और यदि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है, तो दावा न्यायाधिकरण द्वारा बंटवारे के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, कानून के सामान्य सिद्धांतों पर, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के पारस्परिक दायित्व को विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

संदर्भ का उत्तर तदनुसार दिया गया है। अपील को सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष रखा जाए।"

13. हमारी राय में, श्रीमती सुशीला भदोरिया (ऊपर) मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून भी गणेश (ऊपर) और अरुण उर्फ अरविंद (ऊपर) मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसलों के अनुरूप है। हालाँकि, एक ही समय में, यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि भले ही सभी संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं को पक्षकार बनाया गया हो और दोनों चालक गवाह बॉक्स में प्रवेश कर चुके हों और न्यायाधिकरण या अदालत प्रत्येक चालक की लापरवाही की सीमा निर्धारित करने में सक्षम है जो संयुक्त

अपकृत्यकर्ताओं के बीच पारस्परिक दायित्व के प्रयोजन के लिए है, लेकिन उनका दायित्व संयुक्त और अलग रहेगा ताकि वादी/दावेदार को संतुष्ट किया जा सके।

14. अंशदायी और समग्र लापरवाही के बीच अंतर है। अंशदायी लापरवाही के मामले में, एक व्यक्ति जिसने खुद इस हद तक योगदान दिया है, वह अपनी लापरवाही की सीमा तक दुर्घटना में लगी चोटों के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है; जबकि समग्र लापरवाही के मामले में, पीड़ित व्यक्ति ने दुर्घटना में योगदान नहीं दिया है, बल्कि दो या दो से अधिक अन्य व्यक्तियों की लापरवाही के संयोजन का परिणाम है। टी ओ एंथोनी बनाम करवर्नन और अन्य [2008 (3) एससीसी 748] में इस न्यायालय ने माना है कि अंशदायी लापरवाही के मामले में, घायल को प्रत्येक गलत कर्ता की जिम्मेदारी की सीमा को अलग से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, न ही अदालत के लिए प्रत्येक ग़लती करने वाले के दायित्व की सीमा अलग-अलग निर्धारित करना आवश्यक है। यह केवल अंशदायी लापरवाही के मामले में है कि दुर्घटना में घायल ने स्वयं अपनी लापरवाही से योगदान दिया है। उसकी लापरवाही की सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है क्योंकि चोटों के संबंध में उसके द्वारा वसूली योग्य क्षति को उसकी अंशदायी लापरवाही के अनुपात में कम किया जाना चाहिए। प्रासंगिक भाग यहां निकाला गया है:

> "6. 'समग्र लापरवाही' का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ओर से की गई लापरवाही से है। जहां एक व्यक्ति दो या दो से अधिक गलत काम करने वालों की ओर से लापरवाही के परिणामस्वरूप घायल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति उन गलत काम करने

वालों की समग्र लापरवाही के कारण घायल हुआ था। ऐसे मामले में, प्रत्येक गलत कर्ता, संपूर्ण क्षति के भुगतान के लिए घायल के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होता है और घायल व्यक्ति के पास उनमें से सभी या किसी एक के खिलाफ कार्यवाही करने का विकल्प होता है। ऐसे मामले में, घायल को प्रत्येक ग़लती करने वाले की जिम्मेदारी की सीमा अलग से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, न ही अदालत के लिए प्रत्येक ग़लती करने वाले की ज़िम्मेदारी की सीमा अलग से निर्धारित करना आवश्यक है। दूसरी ओर, जहां किसी व्यक्ति को चोट लगती है, आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से लापरवाही के कारण, और आंशिक रूप से अपनी लापरवाही के परिणामस्वरूप, तो घायल के उस हिस्से की लापरवाही, जिसने दुर्घटना में योगदान दिया, को उसकी अंशदायी लापरवाही के रूप में संदर्भित किया जाता है। जहां घायल कुछ लापरवाही का दोषी है, नुकसान के लिए उसका दावा केवल उसकी ओर से लापरवाही के कारण पराजित नहीं होता है, बल्कि चोटों के संबंध में उसके द्वारा वसूली योग्य क्षति उसकी अंशदायी लापरवाही के अनुपात में कम हो जाती है।

7. इसलिए, जब दो वाहन दुर्घटना में शामिल होते हैं, और उनमें से एक चालक लापरवाही का आरोप लगाते हुए दूसरे चालक से मुआवजे का दावा करता है, और दूसरा चालक लापरवाही से इनकार करता है

या दावा करता है कि घायल दावेदार खुद लापरवाह था, तो यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या घायल दावेदार लापरवाह था और यदि हां, तो क्या वह दुर्घटना के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से जिम्मेदार था और उसकी जिम्मेदारी की सीमा, यह उसकी अंशदायी लापरवाही है। इसलिए जहां घायल स्वयं आंशिक रूप से उत्तरदायी है, वहां 'समग्र लापरवाही' का सिद्धांत लागू नहीं होगा और न ही कोई स्वचालित अनुमान लगाया जा सकता है कि लापरवाही 50:50 थी जैसा कि इस मामले में माना गया है। ट्रिब्यूनल को अपीलकर्ता की अंशदायी लापरवाही की सीमा की जांच करनी चाहिए थी और इस तरह समग्र लापरवाही और अंशदायी लापरवाही के बीच भ्रम से बचना चाहिए था। उच्च न्यायालय उक्त त्रुटि को सुधारने में विफल रहा है।"

15. आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम के हेमलता और अन्य [2008 (6) एससीसी 767] में टी ओ एंथोनी बनाम करवर्नन और अन्य (ऊपर) के फैसले पर भरोसा किया गया है।

16. पवन कुमार और अन्य बनाम हरकिशन दास मोहन लाल और अन्य [2014 (3) एससीसी 590] में, टीओ एंथोनी (सुप्रा) और हेमलता (सुप्रा) के फैसलों की पुष्टि की गई है, और इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जहां वादी/दावेदार स्वयं संयुक्त रूप से और अलग-अलग लापरवाह पाया जाता है, वहां दायित्व उत्पन्न नहीं हो सकता है और वादी के दावे को उसकी अपनी लापरवाही की सीमा तक, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, अलग करना होगा। वह अपनी स्वयं की लापरवाही के कारण न होने वाले

नुकसान का हकदार है। अंशदायी के साथ-साथ समग्र लापरवाही के संबंध में कानून/भेद पर इस न्यायालय द्वारा मच्छींद्रनाथ कर्णथ कसार बनाम डीएस मायलरप्पा और अन्य [2008 (13) एससीसी 198] और संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मामले में भी विचार किया गया है। इस न्यायालय ने संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के संबंध में कार्रवाई के कारण के रूप में लापरवाही पर चार्ल्सवर्थ और पर्सी को इस प्रकार संदर्भित किया है:

> "42. चार्ल्सवर्थ और पर्सी ऑन नेग्लिजेंस के 10 वें संस्करण के अनुसार, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं का वर्णन इस प्रकार किया गया है:
>
> नियम के अर्थ के अंतर्गत गलत काम करने वालों को संयुक्त अपकृत्यकर्ता माना जाता है, जहां उनमें से प्रत्येक के खिलाफ कार्रवाई का कारण एक ही है, अर्थात्, समान सबूत उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई का समर्थन करेंगे..... तदनुसार, वे उस अपकृत्य के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हों जो वे दोनों करते हैं या जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं क्योंकि कानून एक ही समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों पर एक ही गलत कार्य करने का आरोप लगाता है। ऐसा (ए) एजेंसी के मामलों में होता है; (बी) परोक्ष दायित्व; और (सी) जहां एक संयुक्त कार्य के दौरान, उनके बीच सहमत एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करते हुए एक अपकृत्य किया जाता है।" सवाल यह भी उठता है कि जिन संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं से मुआवजा वसूल किया गया है, उनके लिए क्या उपाय उपलब्ध हैं। जब अन्य संयुक्त अपकृत्य कर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो स्पष्ट रूप से गैर-अभियुक्त चालक की

लापरवाही का प्रश्न तय नहीं किया जा सकता है, संयुक्त अपकृत्य कर्ता के पक्षकार की अनुपस्थिति में समग्र लापरवाही का विभाजन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह मुआवजे का भुगतान करने के बाद संयुक्त अपकृत्य कर्ता के लिए खुला होगा, ताकि दूसरे संयुक्त अपकृत्यकर्ता पर मुकदमा चलाया जा सके और उससे उसकी लापरवाही की सीमा तक योगदान की वसूली की जा सके। हालाँकि, ऐसे मामले में जब दोनों अपकृत्यकर्ता अदालत/न्यायाधिकरण के समक्ष हैं, यदि साक्ष्य पर्याप्त है, तो यह उनकी लापरवाही की सीमा निर्धारित कर सकता है ताकि एक संयुक्त अपकृत्य कर्ता निष्पादन कार्यवाही में दूसरे संयुक्त अपकृत्य कर्ता से निर्धारित राशि की वसूली कर सके, जबकि दावेदार को दोनों या उनमें से किसी एक से मुआवजा वसूल करने का अधिकार है। इस न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चल्ला भारतम्मा और अन्य [2004 (8) एससीसी 517] में वसूली के तरीके के संबंध में इस प्रकार निर्धारित किया है:

"13. शेष प्रश्न यह है कि उचित दिशा क्या होगी। अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ता के लिए आदेश को संतुष्ट करना उचित होगा, हालांकि कानून में इसका कोई दायित्व नहीं है। कुछ मामलों में बीमाकर्ता को बीमाधारक से राशि वसूलने का विकल्प और स्वतंत्रता दी गई है। मालिक से भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए बीमाकर्ता को मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं

होगी। यह संबंधित कार्यकारी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है जैसे कि बीमाकर्ता और मालिक के बीच विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारण का विषय था और मुद्दा मालिक के खिलाफ और बीमाकर्ता के पक्ष में तय किया गया है। दावेदारों को राशि जारी करने से पहले, उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक उस पूरी राशि के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा जो बीमाकर्ता दावेदारों को भुगतान करेगा। सुरक्षा के एक भाग के रूप में, उल्लंघन करने वाले वाहन को अनुरक्त किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो कार्यकारी न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सहायता लेगा। निष्पादन न्यायालय कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा कि वाहन का मालिक बीमाकर्ता को किस प्रकार भुगतान करेगा। यदि कोई चूक होती है, तो निष्पादन न्यायालय वाहन के मालिक यानी बीमाधारक की किसी भी अन्य संपत्ति या संपत्तियों से या प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों के निपटान के माध्यम से वसूली का निर्देश देने के लिए मुक्त होगा। मौजूदा मामले में शामिल मात्रा पर विचार करते हुए हम यह तय करना बीमाकर्ता के विवेक पर छोड़ते हैं कि वह बीमाधारक से राशि की वसूली के लिए कदम उठाएगा या नहीं।"

17. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नंजप्पन और अन्य [2004 (13) एससीसी 224] में भी, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया है:

"8. इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए हम बलजीत कौर के मामले [2004 (2) एससीसी 1] में कही गई बातों के संदर्भ में निर्देश देते हैं कि बीमाकर्ता ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मुआवजे की मात्रा का भुगतान करेगा, जिसके बारे में आज से तीन महीने के भीतर उत्तरदाताओं-दावेदारों को कोई विवाद नहीं उठाया गया। बीमाधारक से इसकी वसूली के लिए बीमाकर्ता को मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है जैसे कि बीमाकर्ता और मालिक के बीच विवाद ट्रिब्यूनल के समक्ष निर्धारण का विषय था और मुद्दा मालिक के खिलाफ और बीमाकर्ता के पक्ष में तय किया गया है। बीमाधारक को राशि जारी करने से पहले, वाहन के मालिक को एक नोटिस जारी किया जाएगा और उसे पूरी राशि के लिए सुरक्षा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जो बीमाकर्ता दावेदारों को भुगतान करेगा। सुरक्षा के एक भाग के रूप में, उल्लंघन करने वाले वाहन को संलग्न किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो निष्पादन न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सहायता लेगा। निष्पादन न्यायालय कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा कि किस तरीके से बीमाधारक, वाहन का मालिक बीमाकर्ता को भुगतान करेगा। यदि कोई चूक होती है तो निष्पादन न्यायालय को प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों के निपटान या वाहन के मालिक, बीमाधारक की किसी

अन्य संपत्ति या संपत्तियों से वसूली का निर्देश देने का अधिकार होगा। अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों के साथ किया जाता है, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है।"

18. चल्ला भरतम्मा और नंजप्पन (ऊपर) में इस न्यायालय ने मालिक द्वारा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन से निपटा है जब बीमाकर्ता को ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा गया था और उसे वसूलने का अधिकार बीमाकर्ता को संबंधित निष्पादन न्यायालय में दिया गया था, यदि बीमाकर्ता और मालिक के बीच विवाद न्यायाधिकरण के लिए निर्धारण का विषय था और मुद्दा बीमाधारक के पक्ष में तय किया गया है। यही सादृश्य तत्काल मामलों पर भी लागू किया जा सकता है क्योंकि संयुक्त अपकृत्य कर्ता का दायित्व संयुक्त और अलग है। मौजूदा मामले में, संबंधित चालकों के 2/3 और 1/3 की लापरवाही की सीमा तक समग्र लापरवाही की पारस्परिक देयता का निर्धारण होता है। इस प्रकार, वाहन - ट्रेलर-ट्रक जिसका बीमाकर्ता के पास बीमा नहीं था, 2/3 की सीमा तक लापरवाह था। दावेदार को भुगतान करने के बाद बस का बीमा करने वाला बीमाकर्ता निष्पादन कार्यवाही में ट्रेलर-ट्रक के मालिक से उपरोक्त सीमा तक राशि वसूल करने के लिए मुक्त होगा। यदि साक्ष्य के अभाव में पारस्परिक दायित्व का कोई निर्धारण नहीं किया गया था या अन्य संयुक्त अपकृत्यकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया था, तो ऐसे विवाद को निपटाने और निष्पादन कार्यवाही में राशि की वसूली करना संभव नहीं था, लेकिन उपाय एक और मुकदमा दायर करना होगा या कानून के अनुसार उचित कार्यवाही।

उपरोक्त चर्चा से जो बात निकलकर सामने आती है वह इस प्रकार है:

(i) समग्र लापरवाही के मामले में, वादी/दावेदार दोनों या संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से किसी एक पर मुकदमा करने और पूरे मुआवजे की वसूली करने का हकदार है क्योंकि संयुक्त अपकृत्यकर्ता का दायित्व संयुक्त और अलग है।

(ii) समग्र लापरवाही के मामले में, वादी/दावेदार की तुलना में दो अपकृत्यकर्ताओं के बीच मुआवजे का बंटवारा स्वीकार्य नहीं है। वह अपनी इच्छानुसार उनमें से किसी से भी संपूर्ण क्षति की वसूली कर सकता है।

(iii) यदि सभी संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं को पक्षकार बना दिया गया है और साक्ष्य पर्याप्त है, तो यह अदालत/न्यायाधिकरण के लिए खुला है कि वह चालकों की समग्र लापरवाही की सीमा निर्धारित कर सके। हालाँकि, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के बीच लापरवाही की सीमा का निर्धारण केवल उनके पारस्परिक दायित्व के प्रयोजन के लिए है ताकि एक व्यक्ति वादी/दावेदार को पूरा भुगतान करने के बाद दूसरे से उस सीमा तक राशि वसूल कर सके, जिस हद तक उसने दूसरे के दायित्व को पूरा किया है। यदि उन दोनों को पक्षकार बनाया गया है और उनकी लापरवाही का बंटवारा/सीमा अदालत/न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, तो मुख्य मामले में एक संयुक्त अपकृत्यकर्ता निष्पादन कार्यवाही में दूसरे से राशि वसूल कर सकता है।

(iv) अदालत/न्यायाधिकरण के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अन्य संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं को दोषी ठहराए जाने की अनुपस्थिति में दो वाहनों के चालकों की समग्र लापरवाही की सीमा निर्धारित करे। ऐसे मामले में, डिक्री या पुरस्कार पारित होने के बाद पक्षकार संयुक्त अपकृत्यकर्ता पर छोड़ दिया जाना चाहिए, यदि वह चाहे तो, पृथक कार्यवाही में अन्य संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए।

19. परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। पक्षों को होने वाली लागत वहन करनी होगी।

अपीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।